SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, the hon. Member has mentioned that passive and environmental smokers are also getting affected day by day. A proposal is under the consideration of the Government to bring forward a comprehensive legislation which is expected to reduce the use of tobacco in the country. Sir, already a statutory warning is printed on the cigarette packets and cartons. The Government of India is considering to bring forward a comprehensive legislation with regard to these tobacco products also. The Ministry is examining the steps which can discourage the use ot chewing tobacco particularly by the children.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सभापति महोदय, विश्व में जितने ओरल केन्सर होते हैं उनका वन थर्ड हिन्दुस्तान में होता है और हिन्दुस्तान में जितने ओरल केन्सर होते है उनमें 90 प्रतिशत टोबेको च्युइंग की वजह से होता है, खासकर गुटका की वजह से होता है। तो मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपका कोई ऐसा इरादा है इस सर्वनाशी गुटका को बैन करने का? क्या मंत्री महोदय को यह भी पता है कि सन 2020 तक दुनिया में जितनी डैथ होंगी, मौत होगी, चाहे वह कार एक्सीडेंट की वजह से हो चाहे हृदय रोग से हों, चाहे मस्तिष्क रोग से हों, उनसे ज्यादा मौतें होगी सिर्फ तम्बाकू सेवन और सिगरेट के पीने की वजह से? तो क्या इस पर ऐक लगाने का कोई इरादा है आपका, मंत्री महोदय?

SHRI DALIT EZHILMALAI: I really appreciate the concern of the hon. Member regarding banning of gutkha. Banning of gutkha involves three or four Ministries i.e., the Ministry of Industry, the Ministry of Commerce, etc. It also involves tobacco growers, manufacturers, producers, users, exporters, etc. So far as Health Ministry is concerned, we are studying this and in course of time, we will come out with a comprehensive Bill either to ban gutkha or to stop its use.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Agitation by employees of IGNCA

*242. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the 'Dainik Jagaran' dated 23rd May, 1998, regarding arbitrary termination of an employees of IGNCA.

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether procedural enquiry as required under CCS Rules was held before terminating the services of the said employee;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether Government would review the powers of the present Academi Director of IGNCA regarding appointment and termination of services of employees; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Following the termination of services of an office-bearer of the employee's union of IGNCA on 22.5.1998, a large number of IGNCA employees were on strike, demanding his reinstatement as well as redressal of other grievances.

Government asked Member Secretary IGNCA on 8.6.1998 to redress the grievances of the employees amicably. The strike has been withdrawn following reinstatement of the employee in service of IGNCA with effect from 10.6.1998.

(e) and (f) Does not arise.

Discharge of Pollutants by Old Commercial Vehicles

*246. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the commercial vehicles having completed more than 15 years life are mostly discharging pollutants in the atmosphere;

(b) if so, whether the Central Pollution Control Board has failed to check the discharge of pollutants by those outdated commercial vehicles; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) to (c) The quantum of pollutants discharged by a vehicle tends to increase with aging, especially if the maintenance is poor. Checking of commercial vehicles for pollution is, however, a function of the State Transport Authorities who carry out a regular inspection and maintenance programme.

विज्ञान का विकास

*248. **श्री राज बब्बर: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने "जय विज्ञान" का नारा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञान के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने 25 मई, 1998 को आयोजित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वितरण समारोह में अपने भाषण के दौरान वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और सरकार के नीति निर्माताओं के विचारार्थ निम्नवत् विशिष्ट सुझाव देकर "जय विज्ञान" नारे को कार्यान्वित करने हेतु अनेक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की:

(i) विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बनाना;

(ii) सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाना;

(iii) योजना प्रक्रिया के लिए विज्ञान को केन्द्रीय बनाना;

(iv) हमारे युवा वैज्ञानिकों की बौद्धिक और मानसिक निधि में वृद्धि करना तथा प्रतिभावान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मान्यता देना एवं उनका सम्मान करना;

(v) ज्ञान नेटवर्क का सृजन और साहचर्य करना;

(vi) उद्योग में और उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना;

(vii) वैश्विक श्रेष्ठता और नेतृत्व के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में ध्यान फोकस व केन्द्रित करना;

(viii) राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना;

(ix) बौद्धिक संपदा प्रवृत्ति (आन्दोलन) का सृजन करना;

(x) वैज्ञानिक संस्थानों को अफसरशाही से मुक्त करना।

शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों को जोड़ने की पहल आरम्भ की जा चुकी है। उदाहरणार्थ, आम आदमी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता, अंतर्जात संसाधनों में मूल्य अभिवृद्धि और विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने संबंधी आधारभूत मुद्दों की दिशा में कार्य करने हेतु सीएसआइआर के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पूर्वाभिमुखीकरण के लिए विशिष्ट तौर पर कार्य योजना तैयार की गई है। समय और कार्य लक्ष्यों वाले विशिष्ट रणनीति पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी प्रकार सरकार ने इस बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अवसंरचना के उन्नयन हेतु निधि (फिस्ट) नामक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। 40 वर्ष से कम आयु के होनहार युवा वैज्ञानिकों के लिए शीघ्र ही एक विशेष "स्वर्ण जयंती फैलोशिप्स" की घोषणा की जाएगी ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 11 मई को "प्रौद्योगिकी दिवस" के रूप में घोषित किया गया है जो इस बात का द्योतक है कि सरकार राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के महत्व पर बल देती है।

Ban of USA's Anti-Impotency drug 'VIAGRA' in India

*249. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that impotence affects 30% of American males (*vide* Normal Shealy's 'Miracles Do Happen', p. 91, Parliament House Library);

(b) whether it is a fact that in India there is no such problem; and

(c) whether Government, in view of the above, will consider a ben on Cipla's plan (*vide*. Economic Times, dated 19th May, 1998) to introduce USA's anti-impotency drug 'VIAGRA' in India since